

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

‘हर काम देश के नाम’

नई दिल्ली: भाद्रपद 21, 1944

सोमवार: 12 सितंबर 2022

रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय सेना के पहले लॉजिस्टिक्स सेमिनार में कहा, सरकार सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर लॉजिस्टिक्स प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध

प्रणाली को और मजबूत करने तथा भविष्य के खतरों के लिए तैयार रहने हेतु असैन्य-सैन्य सम्मिश्रण का आह्वान किया

साझा लॉजिस्टिक्स नोड्स स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि एक सेवा के संसाधन बाकी सेवाओं को निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सकें: श्री राजनाथ सिंह

सरकार भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने और देश को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक मजबूत, सुरक्षित, त्वरित और 'आत्मनिर्भर' लॉजिस्टिक्स प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 'सामंजस्य से शक्ति' विषय पर आयोजित पहली भारतीय सेना लॉजिस्टिक्स संगोष्ठी में मुख्य भाषण के दौरान यह बात कही।

श्री राजनाथ सिंह ने 2047 तक 'अमृत काल' में भारत को एक महाशक्ति बनाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित ढांचे के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, “भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य में, चाहे युद्ध के मैदान में हो या नागरिक क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स भरण-पोषण की उपयोगिता बढ़ेगी। ऐसे में 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से लॉजिस्टिक्स सिस्टम में सुधार करना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हमें एक 'आत्मनिर्भर' लॉजिस्टिक्स पूर्ति प्रणाली की आवश्यकता है।”

रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता को पिछले कुछ वर्षों में रक्षा मंत्रालय में किए गए प्रमुख नीतिगत बदलावों में से एक बताया, जिससे बोर्ड से आगे के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत लॉजिस्टिक प्रणाली स्थापित करने की नींव रखी गई है, जो सशस्त्र सेनाओं की परिचालन तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो यह सुनिश्चित करता है कि सही गुणवत्ता और मात्रा के साथ सही मर्चे सेना को सही समय और

सही जगह पर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सैन्य रसद एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जो युद्ध के परिणाम को निर्धारित करता है।

दृश्यमान सकारात्मक परिणामों के बारे में विस्तार से बताते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण, भगावत रोधी गतिविधियों से निपटने के साथ-साथ आपदा राहत, मानवीय सहायता, गैर-समाघात निकासी, समाघात खोज एवं बचाव और हताहतों की निकासी प्रतिक्रिया समय में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस संबंध में सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

लॉजिस्टिक्स प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार तीनों सेनाओं की जरूरतों के अनुसार देश में सामान्य लॉजिस्टिक्स नोड्स स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि इन नोड्स के माध्यम से, एक सेवा के संसाधन बाकी सेवाओं के लिए निर्बाध रूप से उपलब्ध होंगे।

श्री राजनाथ सिंह ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सौध-निर्माण पद्धति पर अपने विचार साझा करते हुए इसे कुशल लॉजिस्टिक्स का एक प्रमुख हिस्सा बताया। सभी सेवाओं ने अपनी आईसीटी सौध-निर्माण पद्धति विकसित की है। हमारा प्रयास है कि तीनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन होना चाहिए, ताकि हम अपने संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग कर सकें।

रक्षा मंत्री ने लॉजिस्टिक्स प्रणाली को और मजबूत करने तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने हेतु असैन्य-सैन्य सम्मिश्रण का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य के युद्धों में लॉजिस्टिक्स को न केवल तीनों सेनाओं के बीच, बल्कि औद्योगिक बैक-अप, अनुसंधान और विकास, सामग्री सहायता, उद्योग और मानव-शक्ति के रूप में विभिन्न निकायों के बीच संयुक्तता की आवश्यकता होगी। उन्होंने सिविल और सेना के बीच प्रतिबद्धता और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए मजबूत नीतियां बनाने का आह्वान किया, जो भविष्य के खतरों से लोगों की रक्षा करने के सरकार के दृष्टिकोण को नए सिरे से सशक्त बनाएगा। उन्होंने विभिन्न देशों की नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का सुझाव देते हुए जोर देकर कहा कि असैन्य-सैन्य समन्वय का उच्चतम स्तर केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सभी हितधारक एक मजबूत ढांचे के अंतर्गत एक साथ आएँ।

श्री राजनाथ सिंह ने देश में लॉजिस्टिक्स को एकीकृत करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कई नीतियों पर भी प्रकाश डाला। इन नीतियों में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, पीएम गति शक्ति और अवसंरचना के विकास को सुनिश्चित करने के अन्य प्रयास शामिल हैं।

अपने शुरुआती संबोधन में थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भारत को रक्षा लॉजिस्टिक्स की वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए राष्ट्र के प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मौजूदा प्रयासों से न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि मित्र देशों को भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल

वी आर चौधरी, नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और रक्षा, रेलवे, नागर विमानन, वाणिज्य एवं उद्योग, अर्धसैनिक बलों के अन्य अधिकारी और शिक्षा जगत एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

संगोष्ठी का आयोजन तीन सत्रों में किया गया। "सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण" पर प्रख्यात वक्ताओं और विषय विशेषज्ञों के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों और वाणिज्य एवं शिक्षा जगत के विख्यात परामर्शदाताओं ने 'लॉजिस्टिक्स में बदलाव के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उद्योग' विषय पर चर्चा की। भारतीय सेना के युवा उद्यमियों एवं पूर्वसैनिकों और युवा अधिकारियों ने 'प्रौद्योगिकी के माध्यम से सैन्य लॉजिस्टिक्स की पुनः कल्पना' पर अपने विचार व्यक्त किए। इस आयोजन ने भारतीय सेना के यूट्यूब चैनल के 230 अधिकारियों और छह लाख से अधिक दर्शकों को गहन अधिगम अनुभव और उत्तेजक बातचीत प्रदान की। प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे पर विचार साझा करने के अवसर की सराहना की।

एबीबी/डीएस